



संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल

चौधरिस ट्रोफी- ऑस्ट्रेलिया Vs इंग्लैंड
मैच: फिल सॉल्ट 10 रन बनाकर आउट

चौधरिस ट्रोफी 2025 का चौथा मुकामला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्गढ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है।

मर्यादी की दूसरे मुकामले का टीस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और गंदगंधी करने का फैसला लिया है।

इंग्लैंड ने 3 ओवर में एक विकेट पर 20 रन बना लिए हैं। बेन डेकोट और जेमी स्मिथ क्रीज पर हैं। फिल सॉल्ट 10 रन बनाकर आउट हुए।

■ आर.एन.आई 22296/71 ■ डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14

dainiksandhyaprakash.in

सिंह कंधाना ने कही कि पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आंग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देवद का प्रावधान निर्धारित किया गया है। नरवाई जलाने पर कृषि-सोनों से अलग-अलग तरह से अधिक वसूल जाएगा। इसके तहत दो एकड़ तक खेत में नरवाई जलाने पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ खेत में नरवाई जलाने पर पांच हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक खेत की नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपये का जर्माना देना होगा। दंड वसूलने के लिए संबंधित व्यक्ति, निकाय, कृषक जिनके द्वारा नरवाई जलाना पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई है उनको उपसंचालक कृषि सूचना-पत्र जारी करेगा। सूचना-पत्र को तामिल कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी की होगी।

संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेगा एवं तामिल किए गए सूचना पत्रों की सूची अनुविभागीय कृषि अधिकारी उपसंचालक कृषि को प्रस्तुत करेगा। कृषि विस्तार अधिकारी, संबंधित ग्राम के हल्का पटवारी एवं पंचायत सचिव के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाने से पुलिस बल भी साथ में लिया जा सकता है।

नागरिकों के सुविधा हेतु आधुनिक प्रतीक्षालय का शुभारंभ



भोपाल। सिटी लिंक लिमिटेड नगर पालिक निगम द्वारा शंकरदयाल शर्मा चौराहा रेतघाट पर नागरिकों के सुविधा हेतु आधुनिक प्रतीक्षालय का शुभारंभ महापौर मालती राय,बी.सी.एल.एल डायरेक्टर मनोज राठौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर एम.ई.सी सदस्य आर के सिंह बघेल, राजेश हिंगोrani,श्री जगदीश यादव, जोन अध्यक्ष विनीता विकास सोनी, पूजा शर्मा, मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, अधिकारीगण एवं नागरिक उपस्थित रहे।

एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में डीजी-एनसीसी द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित



भोपाल। डीजी एनसीसी का 11 दिवसीय ड्रोन ट्रेनर कोर्स एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित किया गया। डीजी एनसीसी मुख्यालय द्वारा आयोजित पहला ड्रोन ट्रेनर कोर्स 10 से 21 फरवरी 25 तक एलएनसीटी विश्वविद्यालय, 2 एमपी एयर स्क्वाड्रन, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय भोपाल और एनसीसी निदेशालय एमपी और सीजी के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कोर्स में सभी 17 एनसीसी निदेशालयों से सेना, नौसेना और वायु सेना के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस कोर्स में प्रतिभागियों को ड्रोन बनाना और उड़ाना सिखाया गया। सभी प्रतिभागियों ने लिखित परीक्षा दी और उड़ान का प्रदर्शन किया। ये सभी प्रतिभागी वापस जाकर अपने-अपने निदेशालयों में कैडेटों को प्रशिक्षण देंगे।

सिंधु नव जागरण समिति में राम पारदासानी अध्यक्ष, नरेश चोटरानी महासचिव नियुक्त

संत हिरदाराम नगर। संत हिरदाराम नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था सिंधु नव जागरण समिति के पदाधिकारियों की बैठक समिति अध्यक्ष राम पारदासानी की अध्यक्षता में स्वामी शांतिप्रकाश धर्मशाला में सम्पन्न हुई। जिसमें पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नये पदाधिकारियों के चयन पर विचार किया गया। जिसमें समिति के चुनाव का कार्यकाल दो वर्ष का होता है पदाधिकारियों का चयन समिति के संरक्षक द्वारा किया जाता है। समिति संरक्षक आसनदास वाग्धवानी व माधु चांदवानी समस्त पदाधिकारियों से चर्चा कर एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। जिसमें राम पारदासानी अध्यक्ष, नरेश चोटरानी महासचिव, मुख्य सलाहकार घनश्याम लालवानी, उपाध्यक्ष महेश खटवानी, मुरली गुरबानी, हरीश वलेवा, कोषाध्यक्ष हीरो आडवाणी, सचिव दिलीप दीनानी, सहसचिव मनोहर सोतानी, सामाजिक सचिव राम लेखवानी, सह कोषाध्यक्ष इन्द्र जनयानी, आडिटर अनिल टेकचंदानी, प्रवक्ता महेश दादलानी, सलाहकार कमलेश छुगानी व कन्हैयालाल नागदेव को बनाया गया। समिति के संरक्षक माधु चांदवानी ने बताया कि समिति द्वारा समाज क्षेत्र व धार्मिक क्षेत्र में सेवा कार्य करती है। समिति द्वारा सिंधी समाज का पावन पर्व चौतीचांद विगत 35 वर्षों से भूमधाम से मनाती आ रही है। इस वर्ष भी 1 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक संस्था व सिंधी मेले का आयोजन किया गया है।

निगम ने की 2 बकायादारों की संपत्तियां कुर्क

भोपाल। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार सहित राजस्व की अन्य मदों में करो/शुल्कों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही करों का भुगतान न करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के जोन क्रमांक 08 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28 के सुदामा नगर एवं निवेश नगर में बकायादारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 बकायादारों की संपत्तियां कुर्क की। निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायन द्वारा प्रभावी वसूली एवं बकायादारों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देशों के परिणाम में निगम के जोन क्रमांक 08 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28 के अमले ने सुदामा नगर में भवन क्रमांक 204 पर संपत्तिकर/जल उपभोक्ता प्रभार एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की बकाया राशि 76,708 रुपये का भुगतान भवन स्वामी श्रीमती लीलाबाई द्वारा न किये जाने पर उक्त संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की गई साथ निगम अमले ने वार्ड क्रमांक 28 में ही निवेश नगर में भवन क्रमांक 15 पर संपत्तिकर/जल उपभोक्ता प्रभार/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की बकाया राशि 39,373/-रुपये का भुगतान भवन स्वामी बी.पी.छापरे द्वारा न किये जाने पर उक्त संपत्ति कुर्क की।

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का उद्घाटन



भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का शुभारंभ म.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पूर्व संस्था पर किया गया। सेंटर का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ डॉ. अजय चौबे, डायरेक्टर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर,सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, डॉ. अरूण जोशी, कुलपति, सी.वी.रमन विश्वविद्यालय खण्डवा, रवि चतुर्वेदी, कुलसचिव, डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय खण्डवा, डॉ. संगीता जोहरी, कुलसचिव आर.एन.टी.यू., डॉ. रचना चतुर्वेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री संतोष चौबे ने कहा कि आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में चयनित उद्यमियों को इस सेंटर की क्षमताओं से अवगत कराया जाएगा। इस सेंटर के माध्यम से

उद्योगों और स्टार्टअप को नवाचारों और पेटेंटेड तकनीकों तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जिससे वे उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर अपने व्यवसायों को और अधिक सशक्त बना सकें। निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। डॉ. अजय चौबे ने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर नवाचारों, अनुसंधान और उद्योगों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करेगा, जिससे छात्रों और स्टार्टअप को पेटेंटेड तकनीकों तक सीधा लाभ मिलेगा।

साकार हुआ संस्कृति का सौंदर्य, कथा-कहानियों और परंपराओं का जगमगाया संसार

51वें खजुराहो नृत्य समारोह का दूसरा दिन

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन छतरपुर के सहयोग से आयोजित 51वाँ खजुराहो नृत्य समारोह की दूसरी शाम देश के सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकारों ने कंदरिया महादेव मंदिर की आभा में बने मंच पर संस्कृति के अनूठे रंग दमक उठे। सांझ की धुंधलाती रोशनी में नृत्य का संसार जगमगा उठा और रात होते-होते परवान चढ़ा।

भारतीय कला-संस्कृति का प्रतीक बन चुके खजुराहो के इस मंच पर दूसरी शाम तीन नृत्य प्रस्तुतियां सुधिजनों के सामने आईं। इसमें पहली प्रस्तुति थी सुप्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना और पद्मश्री सुश्री दर्शना झावेरी एवं उनके शिष्यों की। एक ऐसी नृत्यांगना जिसने नृत्य को न सिर्फ किया, बल्कि उसे आत्मसात भी किया। अपनी



गुरु परम्परा को नृत्य के आकाश में बुलंदियों तक लेकर आई। गुरु बिपिन सिंह के मणिपुरी घराने की आला दर्जे की नृत्यांगना ने अपनी प्रस्तुति का आरम्भ पारंपरिक रूप से ईश्वर की वंदना से किया। मंगलाचरण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा को नमन किया। इसके बाद बसंत रास का प्रमुख उत्सव होली मंच पर साकार हुआ। जिसके केंद्र में थे कृष्ण, राधा और गोपियां। होलिका कीडम प्रस्तुति ने सुधिजनों को ब्रज की होली सदृश्य दिखाई। होली के रंगों के बाद मनभजन

जीआईएस में दिखेगी मप्र की सांस्कृतिक विरासत की झलक

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में निवेशकों, उद्योगपतियों और अतिथियों को प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराने के लिए विशेष रूप से संयोजित %अमृतस्य मध्यप्रदेश% नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विविधता और पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को प्रसिध्द कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में 100 से अधिक कलाकार अनूठे रूप में दर्शित करेंगे। इसके साथ ही आयोजन स्थल इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में प्रदेश के पारंपरिक और स्थानीय लोकनृत्य, मटकौ नृत्य, करमा जनजातीय नृत्य आदि की प्रस्तुति एक विशेष आकर्षण होगी।

जीआईएस के दौरान अतिथियों को मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों की संगीतमयी अनुभूति करायी जाएगी। उनके मध्यप्रदेश आने के अनुभव को अविस्मरणीय बनाने के लिए कई मनमोहक कार्यक्रम अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह प्रयास प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयोजन में 23 फरवरी को ताज लेक फ्रंट होटल में शाम 6:30 बजे से बांसुरी, सरोद, सारंगी और जुगलबंदी जैसी संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। समिट के पहले दिन 24 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में सुबह 8 बजे से स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते लोक कला दलों की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

इसी दिन ओडीओपी मंच और मध्यप्रदेश पेवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें गोंड और भील जनजातियों की लोक संस्कृति एवं बुंदेलखंड व चंबल अंचल की विरासत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। शाम को गाला डिनर के दौरान लोकॉचल नृत्य बधाई, मटकी, जनजातीय नृत्य करमा के साथ विशेष अमृत्य मध्यप्रदेश नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर विभिन्न मंचों पर लोकगीत, जनजातीय संगीत और पारंपरिक लोक नृत्य का मंचन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये अतिथि निवेशकों को प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत परंपरा और उससे हमारा जुड़ाव को नजदीक से अनूठे अंदाज में देखने को मिलेगा।

बकानिया से किया समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन

1500 ग्रामीण और 20 से अधिक सरपंच हुए शामिल, किसानों के विकास में निभाएंगे अहम योगदान

संत हिरदाराम नगर। फंदा ब्लॉक के बकानिया गांव में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक परिवर्तन और अर्पण सेवा संस्थान द्वारा किसान और किसानों के विकास के लिए संयुक्त रूप से यह योजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में एचडी बैंक और अर्पण सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के सात 20 परियोजनाओं के सरपंच और 1500 से अधिक ग्रामीण जन शामिल हुए और अर्पण सेवा संस्थान की पूर्ण परियोजनाओं की सफलता से प्रेरणा ली। उद्घाटन सत्र में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आगामी पहलों जैसे जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, कौशल विकास, जैविक कृषि और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों और हितधारकों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए गए, जिससे कृषि उत्पादकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इस पहल को लेकर ग्रामीणों का उत्साह और सकारात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस कार्यक्रम का संचालन श्री विनोद शुक्ला (राज्य प्रमुख - अर्पण सेवा संस्थान, मध्यप्रदेश) ने किया और यह आयोजन एचडीएफसी बैंक, अर्पण सेवा संस्थान और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम



साबित हुआ। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भोपाल के ग्रामीण समुदायों के लिए समावेशी विकास और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम प्रबंधक - अर्पण सेवा संस्थान) एवं फंदा ब्लॉक के 20 परियोजना गांवों के ग्राम सरपंच शामिल थे। इस कार्यक्रम में 1,500 से अधिक किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया।

संत हिरदाराम नगर। संत निरंकारी मिशन की सेवा भावना और मानव कल्याण के संकल्प को साकार करने हेतु 'प्रोजेक्ट अमृत' के अंतर्गत 'स्वच्छ जल, स्वच्छ मन' परियोजना के तृतीय चरण का भव्य शुभारंभ 23 फरवरी को सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं सत्कार योग्य निरंकारी राजपिता रमित के पावन साध्रिय में होगा। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के जोन 24 ए की सभी ब्रांचों के साथ ही भोपाल ब्रांच द्वारा रविवार 23 फरवरी को प्रातः 7 से 10 बजे तक खटलापुरा मंदिर से करिश्मा पार्क छोटा तालाब के किनारे और



बैरागढ़ ब्रांच द्वारा प्रातः 7 से 10 बजे तक झुलेलाल विसंजन घाट के सामने गुलाब उद्यान के समीप तालाब किनारे साफ-सफाई की जाएगी।

संत निरंकारी मिशन ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेरणादायक शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 'प्रोजेक्ट अमृत' का शुभारंभ किया था। संत निरंकारी मंडल के सचिव गोंगिंदर सुखीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वृहद अभियान देशभर में 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में 1600 से भी अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस महाअभियान की यह अभूतपूर्व व्यापकता इसे एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करेगी, जिससे जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश और अधिक प्रभावशाली रूप से जन-जन तक पहुंचेगा।

स्कोप ग्लोबल स्टिकल्स विवि में आयोजित हुआ सम्मान समारोह

भोपाल। राष्ट्रीय विष्णु खरे कविता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन वनमाली सभागार, स्कोप ग्लोबल स्टिकल्स विश्वविद्यालय, भोपाल



परिसर में गरिमामय रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर कला, साहित्य एवं संस्कृति के लिये समर्पित वनमाली सृजनपीठ द्वारा वनमाली जी के शिष्य एवं प्रखर कवि, आलोचक, अनुवादक, पत्रकार विष्णु खरे की स्मृति में राष्ट्रीय कविता सम्मान से चार अलग-अलग श्रेणियों में रचनाकारों को सम्मानित किया गया। विष्णु खरे आलोचना सम्मान से वरिष्ठ आलोचक, कवि, अनुवादक नंदकिशोर आचार्य (बोकानेर), विष्णु खरे अनुवाद सम्मान से वरिष्ठ अनुवादक ए. अरविदाशन (केरल), विष्णु खरे कविता सम्मान से सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, अनुवादक एवं आलोचक लीलाधर मंडलोई (नई दिल्ली) तथा विष्णु खरे युवा कविता सम्मान से युवा कवियत्री सुश्री पार्वती तिकरी (झारखंड) को सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए ख्यात रचनाकार डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि यह समाज का दर्पण और दिशा-सूचक होता है। वनमाली कथा समय और राष्ट्रीय विष्णु खरे कविता सम्मान जैसे आयोजनों की महत्ता इस बात में निहित है कि वे साहित्यकारों और विचारकों को एक मंच पर लाकर समकालीन समाज, उसकी चुनौतियों पर संभावनाओं पर सार्थक विमर्श की प्रेरणा देते हैं। आज सम्मानित होने वाले सभी रचनाकारों ने भी अपनी लेखनी से समाज की संवेदनाओं को स्वर दिया है। इनका लेखन न केवल साहित्य को समृद्ध करता है, बल्कि हमारे समय की जटिलताओं को भी उजागर करता है।

नई सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर 45 किमी पर हेलिपैड और हर 150 किमी पर हवाई अड्डा का करेगी निर्माण



महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। इस कदम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा का समय भी घटेगा, जैसे भोपाल से इंदौर की हवाई यात्रा मात्र 55 मिनट में पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव का मानना है कि विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण मध्य प्रदेश एक प्रमुख एयर कार्गो हब बन सकता है। इसकी क्षमता को देखते हुए, राज्य में 20 से अधिक आधुनिक कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जा रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और

माल परिवहन को सुविधाजनक बनाएंगे। इस नीति से राज्य में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। होटल, परिवहन, विमानन प्रशिक्षण संस्थान, ग्रांडेड स्टाफ और पायलट जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी। सरकार उद्योगों के सतत विकास के लिए भी विशेष कदम उठा रही है। इसमें जीरो लिक्विड डिस्वाज, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और सेंट्रलाइज्ड बेस्ट प्रोसेसिंग के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन अपनाने वाले व्यवसायों को नई ग्रीन कार्ड योजना के तहत त्वरित अप्रूवल और रेगुलेटरी सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले भोपाल को नई नीति के तहत वैश्विक शिक्षण और व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नीति से मध्य प्रदेश देश और दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यापार और पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा।

शिव नवरात्रि के पंचम दिवस भगवान श्री महाकालेश्वर ने श्री छबीना स्वरुप धारण कर भक्तों को दिये दर्शन



उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवनवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भगवान श्री महाकालेश्वर 25 फरवरी 2025 तक अलग-अलग नौ रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। प्रतिदिन अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण स्थित कोटितीर्थ के तट पर प्रातः 08 बजे से श्री गणेश पूजन व श्री कोटेश्वर महादेव भगवान का पूजन-अभिषेक-आरती के साथ शिव नवरात्रि महोत्सव के पंचम दिवस का प्रारम्भ हुआ। श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री महाकालेश्वर भगवान जी का अभिषेक एकादश-एकादशनी रूद्रपाठ से किया गया। अपराह्न में 3 बजे सांध्य पंचामृत पूजन के पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान ने छबिना रूप धारण किया।

शिव नवरात्रि के पाचवे दिन संध्या पूजन के पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर ने श्री छबीना स्वरुप धारण कर भक्तों को दर्शन दिये । भगवान श्री महाकालेश्वर को पीले रंग के नवीन वस्त्र के साथ मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंड-माला, छत्र आदि से सुसज्जित

कर श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान श्री महाकालेश्वर को नागकुंडल एवं फलों की माला में दर्शन दिए 7 शुक्रवार 22 फरवरी 2025 को श्री महाकालेश्वर भगवान श्री होल्कर स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा इस वर्ष नौ दिवसीय नारदीय कीर्तन हेतु पुणे से राष्ट्रीय कीर्तनकार आयुर्वेददाचार्य डॉ.अजय अपामार्जने का कीर्तन प्रतिदिन सायं 05 से 06 बजे तक मन्दिर परिसर मे नवग्रह मन्दिर के पास संगमरमर के चबूतरे पर हो रहा है 7 हरिकीर्तन के पाचवे दिन डॉ. अपामर्जने ने संत शिरोमणि सूरदास महाराज के भजन अवसर बार बार नहीं आवे सुनाया एवं भजन के भावार्थ का वर्णन किया। जिसमे उन्होंने बताया कि मनुष्य मात्र को अनमोल जीवन व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए यह जीवन बड़े पुण्य खर्च करने के बाद ही मिला है इसे भलाई, समाज सेवा, धर्म कार्य, देश कार्य आदि करने में व्यतीत करना चाहिए साथ ही भगवान कि भक्ति से ही जीवन सफल होगा, कथा के दौरान तबला पर संगत श्री श्रीधर व्यास ने की।



कोच्चि। केरल के जाने-माने ईसाई धार्मिक नेता श्री मोन्सी जोसेफ आज आधिकारिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को अपनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफूल पटेल के नेतृत्व में विश्वास जताया है। केरल के प्रदेश अध्यक्ष ए.एन.मोहम्मद कुट्टी, कई राज्य पदाधिकारियों और कोच्चि के सम्मानित सामुदायिक नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव द्वारा उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर, बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि मोन्सी जोसेफ के शामिल होने से केरल में एनसीपी को और मजबूती मिलेगी, जिससे आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों में पार्टी की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने केरल राज्य संगठन की भी सराहना की तथा इस बात पर बल दिया कि यह ए.एन.मोहम्मद कुट्टी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

प्रदेश की एकीकृत टाउनशिप नीति से शहरों का होगा नियोजित विकास

भोपाल। प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। नवीन नीति से प्रदेश में रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के ठोस प्रयास किये जायेंगे। नीति के जरिये प्रदेश में क़िफायती आवास की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नई टाउनशिप नीति से राज्य की सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा। प्रदेश में लैंड पूलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

विभाग द्वारा हाल ही में तैयार की गयी एकीकृत टाउनशिप नीति से रियल एस्टेट के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में अब भूमि मालिक लैंड पूलिंग से एक साथ आकर एकीकृत टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। इससे राज्य में निवेश के अधिक अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अधोसंरचना सुविधाओं में तेजी से विकास होगा। नीति में वर्क सेंटर, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक, कार्यालय, बाजार, आईटी, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मनोरंजन आधारित गतिविधियाँ आदि के प्रावधान रखे गये हैं। इन सबके बढ़ने से राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। वर्तमान में

डेवलपर द्वारा छोटी-छोटी भूमियों पर कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है, जिसके कारण नगर स्तर की अधोसंरचनाएँ विकसित नहीं हो पा रही हैं। तैयार की गयी नई नीति में ऐसे प्रावधान रखे गये हैं, जिससे शहर में सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास हो सकेगा।

नागरिकों की सुविधा के लिये कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत पार्क और खुले स्थान का प्रावधान है, जिससे शहर में हरित क्षेत्र का विकास होगा। एकीकृत टाउनशिप नीति में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिये कुल आवासीय इकाइयों का न्यूनतम 15 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान से राज्य के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग की आवास की ज़रूरत पूरी होगी।

नीति के क्रियान्वयन के लिये साधिकार समिति

एकीकृत टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन के लिये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिये प्रमुख सचिव शहरी विकास और आवास की अध्यक्षता में कमेट्री गठित की गयी है। ऐसे जिले जहाँ 5 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं, वहाँ कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। समिति में नगर तथा ग्राम निवेश, शहरी निकाय

दिल्ली सरकार बनने के बाद मप्र में संगठन, सरकार और प्रशासन से जुड़े 3 लंबित फैसलों पर अब लगेगी मुहर

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। वहां मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने भी शपथ ले ली। अब बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेताओं को राज्यों के उन रुके हुए कामों को हरी झंडी दिखाना है, जो दिल्ली चुनाव की वजह से रुके हुए थे। इनमें मध्यप्रदेश के भी कई मामले हैं जिनका अब निराकरण होगा। बीजेपी संगठन स्तर से सरकार और प्रशासन तक के कई फैसले रुके हुए हैं, जिनका रास्ता अब खुलेगा। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी प्रदेश सरकार की व्यस्तता का कारण है, उसके बाद कई रुके हुए फैसलों पर दिल्ली से

मुख्यमंत्री डॉ. यादव लॉन्च करेंगे बायो फ्यूल योजना

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव बायो फ्यूल योजना पेश करेंगे, जो पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो भोपाल में 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस समिट में भारत और विदेशों से उद्योगपति, निवेशक और उद्यमी भाग लेंगे। समिट के दौरान कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इफ्स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विजन के तहत बायो फ्यूल योजना प्रमुख होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि इस योजना को लद्दू-2025 में प्रस्तुत किया जाएगा। यह योजना पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है और यह प्रधानमंत्री मोदी के 'सुदृढ़' अभियान के सिद्धांतों पर आधारित है। इस योजना में बायो सीएनजी, बायोमास ब्रिकेट और पेलेट, तथा बायोडीजल जैसे हरित ईंधन शामिल हैं। सरकार बायो फ्यूल यूनिट स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये तक का निवेश प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, सड़क, जल निकासी और कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए भी 5 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

मुहर लगेगी। मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव होने की संभावना लंबे समय से जताई जा रही थी। उन अटकलें हुए कामों को अब गति मिलेगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मामला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा। वीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हुए लंबा वक्त बीत गया, अभी तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। कुछ नाम मामले हैं, पर किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये फैसला दिल्ली से होगा। दूसरा मामला है, मंत्रिमंडल में हल्के से फेरबदल का। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होना तय है। साथ ही सवा साल के परफॉर्मेंस के आधार पर 3-4 मंत्रियों के भविष्य का

सभी मंत्रियों का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि मुख्यमंत्री ने 18 फरवरी को राज्यपाल से सौजन्य भेंट की थी। समझा जा रहा है कि इसमें इस मुद्दे पर भी कोई बात हुई होगी। वे फैसले जो पार्टी के दिल्ली हाईकमान की मुहर की वजह से रुके हुए हैं, उनमें एक निगम, मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्तियों का भी है। अब इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है। मोहन यादव सरकार के गठन की करीब सवा साल हो गए, लेकिन अभी तक निगम, मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सियाँ खाली पड़ी है। ये फैसला गुटীয় संतुलन और पार्टी के हाशिये पर पड़े नेताओं को संतुष्ट

उप मुख्यमंत्री देवड़ा और शुक्ल ने बागेश्वर धाम में कैसर अस्पताल एवं सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का किया निरीक्षण

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कैसर अस्पताल का भूमि पूजन



सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से भेंट कर आगामी 23 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित कैसर अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री द्वय ने बागेश्वर धाम में बालाजी भगवान के दर्शन किए और प्रदेश की समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। बागेश्वर धाम परिसर में अत्याधुनिक कैसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23

फरवरी को करेंगे। इस अस्पताल से प्रदेश के हजारों मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूर्ण की जाएँ।

251 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह: बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह भी कार्यक्रम 26 फरवरी को आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु शामिल होंगी। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले इस भव्य विवाह कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की कन्याओं के विवाह

मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित होने के बावजूद छावा के टिकट पर कोई छूट नहीं

भोपाल। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित किए जाने के बावजूद उज्जैन में फिल्म छावा के दर्शकों से टैक्स वसूला जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर अब तक इसका पालन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित फिल्म 'छावा' को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित



दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फिल्म 'छावा' को टैक्स फ्री घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित पीवीआर में दर्शकों से अभी भी पूरा टैक्स वसूला जा रहा है।

किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उज्जैन में दर्शकों से टैक्स वसूला जा रहा है। बुधवार को जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फिल्म 'छावा' को टैक्स फ्री घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित पीवीआर में दर्शकों से अभी भी पूरा टैक्स वसूला जा रहा है।

शुक्रवार को फिल्म देखने पहुंची एक महिला ने दो टिकट खरीदे, जिन पर 40 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक टैक्स फ्री को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इसी कारण दर्शकों से पूरा शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही आधिकारिक मेल प्राप्त होगा, टिकट दरों में आवश्यक कटौती की जाएगी।

निजी गाड़ियों पर हटर और सायरन के खिलाफ दिग्विजय सिंह हाईकोर्ट जाएंगे

डीजीपी को पत्र लिखा

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

प्राइवेट गाड़ियों पर हटर और सायरन लगाकर रौब झाड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर निशाना साधा। यदि उनके पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं, ताकि इस पर रोक लगे। पूर्व सीएम ने डीजीपी को लिखे लेटर में कहा कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध निजी वाहनों में हटर का दुरुपयोग करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता बिना पात्रता के वाहनों पर हटर लगाकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रकरण दर्ज



किए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि बिना किसी राजनैतिक दबाव में आए पुलिस, प्रदेश को हटरों के चलन से मुक्ति दिलाएगी।

दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि पुलिस द्वारा सख्ती से कार्यवाही नहीं किए जाने से छुटभैया नेता आमजन पर रोब जमा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत

पुलिस की गाड़ियों सहित फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में ही हटर का इस्तेमाल किए जाने का नियम है। इन वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन का हटर लगाना प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति बिना पात्रता के वाहनों पर हटर लगाता है, तो चालान बनाकर वाहन जब्त किए जाने चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजधानी

भोपाल सहित अन्य शहरों में हटर लगी गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपराधिक तत्व तक गाड़ियों में हटर लगाकर विशिष्ट श्रेणी में दिखाने का आतंक फैला रहे है।

पुलिस बल भी स्थानीय नेताओं के दबाव में सख्त कार्यवाही करने से पीछे हट जाते है। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि हटर लगाकर घूमने वाले लोग अपनी गाड़ियों पर अनेक संगठनों के पदनाम भी लिखवा लेते है। विधायक, सांसद से लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सहकारी संगठन, सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि तक गाड़ियों पर नंबर प्लेट की जगह पदनाम की बड़ी-बड़ी पट्टिका लगाकर पुलिस बल को चुनौती देते दिख रहे हैं। ऐसे तत्वों की अराजकता के चलते कई बार ट्रैफिक जाम तक की स्थिति बनती है।

लोक निर्माण मंत्री के निर्देश पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कड़ी जांच

भोपाल। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की नवीन पहल प्रारंभ की गई है। इससे तहत हर माह की 5 और 20 तारीख को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से चयनित दलों, जिलों, निर्माण कार्यों और सामग्री के सैंपल लेने के स्थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

मंत्री सिंह के निर्देशानुसार हाल ही में लोक निर्माण विभाग के सातों परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता के सात दलों द्वारा सात जिलों में किया गया जिसमें कुल 35 कार्यों को रेंडम आधार पर चयनित किया गया।इन 35 कार्यों में से 14 कार्य पी.डब्ल्यू.डी. सड़क/ पुल, 12 कार्य पी.आई.यू., 6 कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम, 01 कार्य म.प्र. भवन विकास निगम एवं 02 कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (एन.एच.) का

शामिल किया गया। एक-एक जिले में मुख्य अभियंताओं की टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के बाद प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निरीक्षण किए गए सात जिलों के 35 निर्माण कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया। बैठक में प्रमुख अभियंता (बी.एण्ड आर), उपसचिव म.प्र. शासन, लोनिवि, समस्त मुख्य अभियंता एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे।

नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत बनवारी से तरौनकला सिमारा डापका मार्ग निरीक्षण में पाई गई कमियों के कारण संजय रायकवार कार्यपालन यंत्री नर्मदापुरम को कारण बताओं सूचना पत्र एवं आर.पी. शर्मा अनुविभागीय

अधिकारी व कैलाश गुरदे उपयंत्री को निलंबित तथा ठेकेदार मेसर्स बिंदल डेवलपर्स को कालीसूची में दर्ज करने हेतु मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया। कटनी-बरही-इंदवार-ताला मार्ग परफार्मेंस गारंटी के अंतर्गत ठेकेदार के द्वारा सम्पूर्ण मरम्मत कार्य नहीं करने के कारण स्वर्णकार संभागीय प्रबंधन म.प्र. सड़क विकास निगम शहडोल की एक वेतन वृद्धि अर्सचयी प्रभाव से रोकने तथा ठेकेदार मेसर्स टी.बी.सी.एल को कालीसूची में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। झाबुआ शासकीय महाविद्यालय पेटलावद में 6 अतिरिक्त आध्ययन कक्ष निर्माण कार्य में अनियमितता पर अलसिंह भिडे कार्यपालन यंत्री (भवन) को कारण बताओं सूचना पत्र जारी एवं ठेकेदार मेसर्स वीनस कंस्ट्रक्शन राजगढ़ जिला धार को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिये गये।



इन विशेषताओं में दुनिया को आकर्षित किया

- 5 आईटी एसईजेड और 15 से अधिक आईटी पार्क प्रदेश में एक मजबूत प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं।
- राज्य में 50 से अधिक बड़ी आईटी कंपनियां संचालित हैं, जो एक मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान करती हैं।
- प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हैं।
- राज्य से लगभग 1200 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप और 2 यूनिर्कॉर्न उमरे हैं।
- राज्य भर में 300 से अधिक कॉलेज तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं।
- स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा धारकों सहित सालाना 50 हजार से अधिक तकनीकी स्नातक।
- डेटा केंद्रों और आईटी क्षेत्र के लिए 24/7 विरवसनीय बिजली आपूर्ति और कच्चे माल की उपलब्धता।
- कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का 27% नवीकरणीय स्रोतों से आता है। उद्योगों के लिए खुली पहुंच की अनुमति है।

मध्यप्रदेश तेजी से आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश का केन्द्र बना



इसलिए मप्र हैं पसंदीदा राज्य

- व्यापार-समर्थक नीतियां: वैश्विक तकनीकी मांगों का समर्थन करने के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन।
- भारत में टियर-2 शहरों का गतिशील तकनीकी केंद्रों के रूप में उदय, कार्य और नवाचार के भविष्य को नया स्वरूप देना - इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर।
- लागत प्रभावी संचालन, कार्य जीवन संतुलन, उच्च जीवन स्तर।
- स्टार्टअप विकास: नवाचार के लिए पर्याप्त अवसरों के साथ एक बेहतर इकोसिस्टम।

राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी मध्यप्रदेश

- मध्यप्रदेश का जीएसडीपी भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करता है।
- उमरते आईटी/ ईएसडीएम निर्यात का लक्ष्य भारत के 220 लाख करोड़ रुपए के मजबूत निर्यात बेचमार्क को ध्यान में रखते हुए आगे वृद्धि करना है।
- मध्यप्रदेश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र 5 लाख करोड़ रुपए का योगदान करते हैं, जो भारत के 465 लाख करोड़ रुपए की तुलना में स्थिर वृद्धि दर्शाता है।

24 एवं 25 फरवरी को होगा समित



24 एवं 25 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान एमपी मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन होगा। यह प्रमुख कार्यक्रम राज्य की ऑटोमोटिव क्षेत्र में हुई प्रगति को प्रदर्शित करेगा। नवाचार और स्थिरता पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ एक्सपो का उद्देश्य मध्यप्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और भविष्य के परिवहन समाधानों के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मध्यप्रदेश ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। राज्य 30 से अधिक मूल उपकरण निर्माताओं और अग्रणी पीढ़ी की मोबिलिटी पर मजबूत जोर देने के साथ-साथ टिकाऊ और नवाचार वाले भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश वाणिज्यिक वाहनों और कृषि उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में एक शीर्ष राज्य है। प्रदेश की औद्योगिक सहायक नीतियों और अपने मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे ने ऑटोमोटिव उद्योग के कई दिग्गजों को आकर्षित किया है।



भारत का हृदय मध्यप्रदेश खनिज संपदा और खनन क्षमता का एक पावर हाउस है। अद्वितीय खनिज भंडार और रणनीतिक नीति समर्थन के साथ राज्य खनन और खनिज आधारित उद्योगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। कोयले से लेकर हीरे तक मध्यप्रदेश भारत के भूमिगत खजानों को अनलॉक करने में अग्रणी है। राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। यह भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, पन्ना रत्न-श्रेणी के हीरे के खनन के वैश्विक केंद्र के रूप में चमक रहा है। भारत के कोलबेड मीथेन (सीबीएम) भंडार के 36% के साथ मध्यप्रदेश राष्ट्र की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतना, रीवा और सीधी जैसे जिलों में फैले चूना पत्थर के भंडार तेजी से बढ़ते सीमेन्ट उद्योग की पूर्ति करते हैं, जबकि बालाघाट भारत के 73% भंडार के साथ तांबे के उत्पादन में अग्रणी है। मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट और रॉक फॉस्फेट जैसे प्रमुख संसाधन राज्य की प्रोफाइल को और बढ़ाते हैं, जबकि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, ग्लूकोनाइट और टिन में समाविष्ट खोज गतिविधियों का पता चलता है। बैतूल और सीधी जैसे जिलों में ग्रेनाइट की उपस्थिति इस्पात और ऑटोमोटिव क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति करने की क्षमता बताती है।

कोयले से लेकर हीरे तक मध्यप्रदेश भूमिगत खजानों में भी अग्रणी

समृद्ध खनिज संपदा

पूरा मध्यप्रदेश खनिज संपदा से भरा पड़्डा है। ग्वालियर और शिवपुरी में आयरन और क्रॉडज और फ्लैगस्टोन पाया जाता है। झाबुआ और अलीराजपुर में रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज और ग्रेनाइट मिलता है। नीमच में लाइमस्टोन, बैतूल में कोल, ग्रेनाइट ग्रेनाइट, लेड और जिंक मिलता है। छिंदवाड़ा में कोल, मैंगनीज और डोलोमाइट मिलता है। बालाघाट में कोपर, मैंगनीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मंडला और डिंडोरी में डायमंड, डोलोमाइट और बॉक्साइट, सिंगरौली में कोल, गोलड, आयरन और शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में कोल, कॉल बेड मीथेन, बॉक्साइट, सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट डायस्पोर, आयरन और ग्रेनाइट मिलता है। जबलपुर में डोलोमाइट, आयरन अयस्क, लाइमस्टोन, मैंगनीज, गोलड और मार्बल मिलता है। देश में कोयला का उत्पादन 3 लाख 61 हजार 411 मीट्रिक टन है। मध्यप्रदेश में 30 हजार 916 मीट्रिक टन कोल रिजर्व है, जो देश का 8 प्रतिशत है। इसी प्रकार चूना पत्थर देश में 19028.5 मीट्रिक टन है और मध्यप्रदेश में 1692 मीट्रिक टन है, जो देश का 9% है। लौह अयस्क देश में 6209 और मध्यप्रदेश में 54.1 मीट्रिक टन है, जो देश का एक प्रतिशत है।



जैसे-जैसे भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, मध्यप्रदेश में खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। शाहडोल और सिंगरौली में कोयला भंडार थर्मल बिजली उत्पादन के लिए अपरिहार्य हैं। भले ही राज्य हरित विकल्पों की खोज कर रहा हो। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति से प्रेरित तांबे की बढ़ती

मांग मध्यप्रदेश को तांबा शोधन और संबद्ध उद्योगों के केंद्र के रूप में स्थापित करती है। राज्य खोज में अत्याधुनिक तकनीकों का भी लाभ उठा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) जैसी एजेंसियां नए खनन ब्लॉकों की क्षमता को अनलॉक करने के सर्वेक्षण कर रही हैं।

एक उज्ज्वल भविष्य

मध्यप्रदेश की रणनीतिक स्थिति, कुशल कार्यबल और खनिज बहुतायत निवेशकों के लिए अवसर का एक अनुकूल त्रिकोण बनाते हैं। मजबूत नीति समर्थन और बुनियादी ढांचे के साथ राज्य भारत के खनन और खनिज क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधन न केवल संसाधनों बल्कि विकास, नवाचार और स्थिरता की क्षमता रखते हैं। यह जीवंत खनन परिदृश्य वैश्विक निवेशकों को इसकी परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आकर्षित करता है। 25 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश संवर्धन कार्यक्रम इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 खनन क्षेत्र पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। खनन शिखर सम्मेलन खनन और इससे संबंधित उद्योगों, तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम है। राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों के उपयोग पर ध्यान देने के साथ-साथ शिखर सम्मेलन नियामक ढांचे और तकनीकी प्रगति पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। यह मंच सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों को इस क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक साथ लाएगा, जो मध्यप्रदेश को खनन और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

खनिज संपदा से परिपूर्ण मध्यप्रदेश

- भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य
- तांबा अयस्क और मैंगनीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक
- देश के शीर्ष खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल:
- रॉक फॉस्फेट (दूसरा)
- चूना पत्थर (तीसरा)
- कोयला (चौथा)

खनिज ब्लॉक नीलामी में उपलब्धियाँ

- पहला पुरस्कार: जनवरी 2024 में राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वाधिक ब्लॉक नीलामी के लिए सम्मानित।
- पहला पुरस्कार: जुलाई 2022 में भारत सरकार से प्रमुख और गोण खनिजों के लिए।
- दूसरा पुरस्कार: जुलाई 2022 में भारत सरकार से लौह अयस्क, चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए।
- 78 ब्लॉक: अब तक सफलतापूर्वक नीलाम, यह सभी राज्यों के बीच मध्यप्रदेश का एक रिकॉर्ड है।



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

जीआईएस में प्रधानमंत्री लांच करेंगे प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक नीतियां

विभिन्न श्रेणियों में अब तक हुए 31 हजार 659 से अधिक पंजीयन



भोपाल। 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के मुख्यवर्षित बेहतर आयोजन के लिए गठित शीर्ष समिति की बैठक मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बताया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे दो दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ कर मध्यप्रदेश की सभी नवीनतम औद्योगिक नीतियों की लॉन्चिंग भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जीआईएस परिसर में स्थापित किये जाने वाले एमपी एक्सपीरियंस जोन का अवलोकन भी करेंगे। इस जोन में इमर्सिव डिजिटल वॉक-थ्रू के रूप में मध्यप्रदेश की विरासत, अब तक की प्राप्ति और भावी आकांक्षाओं का समन्वित संयोजन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस को भव्य, सुव्यवस्थित और परिणामदायी बनाने के लिए सभी विभाग बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य से कार्य करें।

आयोजन को बनाएं ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देशित किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसीलिए आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जायें। जीआईएस के आयोजन में प्रबंधन संबंधी कोई भी कमी न रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की और

अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को सहज आकर्षित करने के लिए राज्य की सभी निवेशक हितैषी औद्योगिक नीतियों, म.प्र. में उद्योगों के लिए उपलब्ध व्यापक अधोसंरचनाओं और संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए निवेशकों को वांछित सभी जरूरी सहायता एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

देश-विदेश से आने वाले निवेशक हमारे विशेष अतिथि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस में देश-विदेश से भोपाल आने वाले निवेशक हमारे विशेष अतिथि हैं, इसलिए उनका स्वागत व अभिनंदन विशुद्ध भारतीय आतिथ्य परम्परा से किया जाए। इन दो दिनों को स्मरणीय बनाने के लिए मध्यप्रदेश की संस्कृति, यहां की सत्कार परम्परा, विभिन्न कला उत्पादों सहित यहां के खान-पान, व्यंजन आदि का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाए, जिससे निवेशक दो दिन मध्यप्रदेश में रहने के शानदार अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने भोपाल के तालाबों एवं पूरे शहर का आकर्षक सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी झील में पाल-नौकायन और ई-बैटरी से चलित नौकाओं का संचालन किया जाए, जिससे निवेशक और दूसरे प्रतिभागी भोपाल के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का लुफ्त ले सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि इस समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

जीआईएस में लोकल उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल मंच

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि «एक जिला-एक उत्पाद» हमारे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्स-पो माध्यम से हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच देने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह एक्स-पो न केवल हमारे कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करेगा।» मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में «एक जिला-एक उत्पाद» एक्स-पो प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय शिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

ओडीओपी जोनन परंपरा और नवाचार का संगम- एक्स-पो में प्रदेश के 38 ओडीओपी उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जिन्हें लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया है। लाइव काउंटर में बाघ प्रिंट, जरी जरदोजी, बाटिक प्रिंट, कालीन, चंदेरी साड़ी, बांस, बलुआ पत्थर और कपड़े की जैकेट जैसे आठ प्रमुख उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को कारीगरों द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रतिनिधि और अतिथि कारीगरों के मार्गदर्शन में खुद भी इन उत्पादों को बनाने का अनुभव ले सकेंगे।

‘कुम्हार पुरा’ और ‘टैक्निकल जोन’ - मानव संग्रहालय में मिट्टी के बर्तन और धातु कला के लाइव काउंटर भी आकर्षण का केंद्र होंगे। खाद्य और कृषि उत्पादों की झलक- एक्स-पो में खाद्य, मसाले और फलों से जुड़े 32 ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल पर उनकी निर्माण प्रक्रिया के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

जीआईएस में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर होगा मंथन

उद्योग संघ के प्रतिनिधि एवं उद्योगपति साझा करेंगे अपने अनुभव

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, निवेशक और विशेषज्ञ मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर मंथन करने के लिए एक मंच पर जुटेंगे। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल, मैनुफैक्चरिंग, नवकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर, खाद्य प्र-संस्करण, स्टार्ट-अप्स, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन आदि क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं। समिट में मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और संभावनाओं और अवसरों का लाभ उठाने के लिये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के दिग्गज उद्योगपति अपने अनुभव, विचार और रणनीतियां साझा करेंगे।

औद्योगिक नीति एवं शासन स्तर पर प्रयास

समिट में वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव, फार्मा विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री डी. वी. गनवरी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, खनिज विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव आदि अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही जीएसआई के अपर महानिदेशक श्री धीरज कुमार, राष्ट्रीय शहरी मामलों के सचिव श्री निदेशक श्री हितेश वैद्य और अन्य विशेषज्ञ भी मध्यप्रदेश में उद्योगों के विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

टेक्सटाइल और मैनुफैक्चरिंग

मध्यप्रदेश टेक्सटाइल और मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। राज्य की अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण कई बड़ी कंपनियां यहां निवेश को प्रार्थमिकता दे रही हैं। समिट में टीडब्ल्यूई ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री इंगो सोलर, एईपीसी के महासचिव श्री मिथिलेश्वर ठाकुर, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के चेयरमैन श्री रिजू झुनझुनवाला, सेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक श्री रीनिश सेखानी और प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री श्रेयस्कर चौधरी टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।



स्टार्ट-अप्स और नवाचार

स्टार्ट-अप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनोवुफ के संस्थापक एवं सीईओ श्री वैदंत जैन, स्टार्ट-अप मिडिल ईस्ट के संस्थापक एवं सीईओ श्री सिबी सुधाकर, दुबई स्थित सैव की संस्थापक श्रीमती पूर्वी मुनोत, एम-कैफीन एवं हाइड्रो के सह-संस्थापक श्री तरुण शर्मा और स्क्रिप्स के चांसलर श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे युवा उद्यमी और निवेशक इस क्षेत्र में नए अवसरों पर मंथन करेंगे।

हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर

मध्यप्रदेश फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र में सहजना एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष श्री राजीव छिब्बर, इन्वोल्यूशन हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक श्री गौरव अग्रवाल, बायो-मेरियु इंडिया के प्रमुख श्री बिवाश चक्रवर्ती, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्लोबल हेड ऑपरेशंस श्री राहुल अवस्थी और आईपीसीए लेबोरेट्रीज के प्रबंध निदेशक श्री अजीत कुमार जैन विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

वित्त एवं निवेश

मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के कारण वित्तीय क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। बीम्स फिनटेक के संस्थापक श्री अनुज गोलेचा, एक्वा निमिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी के प्रबंध भागीदार श्री राजेश सहगल, आईटीआई ग्रोथ फंड के जनरल पार्टनर श्री मोहित गुलाटी, यूनिफॉर्न इंडिया वेंचर्स के प्रबंध भागीदार श्री भास्कर मजूमदार और डन एंड ब्रैड स्ट्रीट इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री अविनाश गुप्ता राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

पर्यटन , हॉस्पिटैलिटी

मध्यप्रदेश का पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इस क्षेत्र में ताज होटल्स, रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस के सीईओ श्री पुनीत चटवाल, वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड के अध्यक्ष श्री शिवदास एम और एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र के विशेषज्ञ श्री अजीत बजाज शामिल हैं। बिग बॉस के वॉयस आर्टिस्ट श्री विजय विक्रम सिंह भी समिट में विशेष प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 लिखेगी प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय

घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिये सुनहरा अवसर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीआईएस में जुट रहे निवेशकों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है। पॉलिसी के नवाचारों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाकर आपूर्ति दक्षता को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में दक्ष, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से स्थाई विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करना है, जिससे वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम किया जा सके। इससे प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए आकर्षक स्थल बन सकेगा।

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आगामी वर्षों में इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।



इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से बढ़ेगी परिवहन दक्षता

अन्तर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार 20 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित कर रही है। इससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो माल ढुलाई को सुगम बनाएंगे। परिवहन लागत कम होने से व्यवसायियों का लाभ बढ़ेगा और प्रदेश में अधिक निवेश आकर्षित होगा।

निर्यात क्षमता बढ़ाने विकसित होगा विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का एक महत्वपूर्ण अंग राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाना भी है। इसके लिए पॉलिसी में निर्यात पार्क विकसित किए जाने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। इन पार्कों के विकास को स्टॉप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अधिकतम 40 करोड़ रुपए अथवा प्रति एकड़ 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

पॉलिसी में निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा, निर्यात-उत्मुख इकाइयों की दक्षता बढ़ाना और सुदृढ़ निर्यातोनमुख लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। पॉलिसी के उद्देश्यों में निर्यात की मात्रा बढ़ाना, «मेड इन मध्यप्रदेश» उत्पादों के निर्यात मूल्य में वृद्धि करना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन भी शामिल है।

लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से व्यापारियों और उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। बेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में लाखों नई नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर परिवहन और भंडारण सुविधाएँ मिलेंगी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर चल रही 2000 बैच की आईएसएस अधिकारी को सरकार में महत्वपूर्ण प्रभार देने पर राज्य में विवाद

रांची। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर चल रही आईएसएस अधिकारी पूजा सिंघल को आयकर विभाग का सचिव और झारखंड कम्प्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किए जाने से राज्य में विवाद खड़ा हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कानूनी आपत्तियों के बावजूद, जिसने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में एक आवेदन दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें किसी भी विभाग में नियुक्त न किया जाए, राज्य सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रभार दे दिए। ED को इस बात की चिंता है कि यदि सिंघल को कोई आधिकारिक पद दिया गया तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकती हैं तथा चल रहे मामले को प्रभावित कर सकती हैं। 2000 बैच की आईएसएस अधिकारी सिंघल को खुंटी में मनरेगा के करोड़ों रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 28 महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें 7 दिसंबर 2024 को रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी। उनकी रिहाई के बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन रद्द कर दिया और उसी तारीख से उन्हें बहाल कर दिया। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। भाजपा ने ईडी की आपत्तियों के बावजूद पूजा सिंघल की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सी.पी. सिंह ने इस कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य के खजाने को लूटने के आरोपियों को फिर से महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। जेएमएम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सिंघल केवल आरोपी हैं, दोषी नहीं हैं और बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। जेएमएम प्रवक्ता सुनील पांडे ने कहा कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से उनकी पोस्टिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पांडे ने यह भी बताया कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान, सजल चक्रवर्ती और प्रदीप कुमार जैसे जांच का सामना कर रहे दूरे अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी।

हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर रद्द की

शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. लज्जा राम बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरोपों में कानूनी योग्यता का अभाव है। यह मामला 9 मई, 2024 को निलंबित पुलिस अधिकारी गैब्रियल के. लैंगरई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है , जिसमें बिश्नोई पर अपने सरकारी वाहन के पंजीकरण नंबर का दुरुपयोग करने और उससे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। एफआईआर में आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत आरोप शामिल थे। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए मामले को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया है। बिश्नोई ने मई, 2022 में मेघालय डीजीपी का पदभार संभाला था।

इंदौर में 32वां अंतरराष्ट्रीय मैनेजमेंट कॉन्वलेव 2025: दृष्टिकोण और नवाचार

इंदौर, एजेंसी। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 32वें अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन 2025 का सफल उद्घाटन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में किया, जिसमें 3,000 से अधिक उद्योग जगत के नेता, उद्यमी, नीति निर्धारक, अर्थशास्त्री और अकादमिक एवं छात्र एकत्र हुए, और व्यापार के विकास, वित्तीय उन्नति, नेतृत्व रणनीतियों और भारत की वैश्विक आकांक्षाओं पर परिवर्तनकारी चर्चाएँ कीं। इस वर्ष का थीम उद्यामेना ही सिद्धयंती (स्पृष्टत्व, ड्राइव और ध्राव) था, जिसे डॉ. संदीप आत्रे ने स्पष्ट रूप से समझाया, जिसमें उन्होंने आज के गतिशील व्यापारिक वातावरण में प्रयास और उपलब्धि की महत्ता पर जोर दिया। सम्मेलन की शुरुआत एक आध्यात्मिक और शास्त्रीय छाप के साथ हुई, जिसमें सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन हुआ। आईआईएम इंदौर के निदेशक और इंदौर प्रबंधन संघ के अध्यक्ष डॉ. विमार्शु राय ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य की बात की। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उच्च कुशल कार्याबल द्वारा संचालित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अस्थिरता, अप्रत्याशितता, गैर-रेखीयता और अप्रत्यक्षता , लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में कठिन कार्य की महत्ता पर जोर दिया। भारत 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत कुशल श्रम में दुनिया का नेतृत्व करेगा। एआई और बायोटेक भारत की सुपर-एडवांस्ड स्वास्थ्य सेवा को चलाएंगे। भारत एक वैश्विक आईटी महाशक्ति बनेगा। एआई ईसानों की जगह नहीं लेगा, लेकिन जो एआई से अनजान होंगे, वे प्रतिस्थापित हो सकते हैं। हम सभी के पास कम उपभोग करने की शक्ति है। केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती; परिश्रम, समर्पण और धैर्य भी जरूरी हैं।

सनम तेरी कसम दोबारा रिलीज के बाद भी चार्ट्स पर सुपरहिट

मुंबई, एजेंसी। सनम तेरी कसम, जो एक पसंदीदा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, 7 फरवरी 2025 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह इसकी पहली बार हुई रिलीज के नौ साल पूरे होने का खास मौका था। पहली बार जब यह रिलीज हुई थी, तब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन समय के साथ, फिल्म को एक खास फैनबेस मिला, जहां लोग इसकी भावनात्मक कहानी और सुरिले संगीत से गहराई से जुड़ गए। फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता के कारण, फैंस ने इसकी दोबारा रिलीज की मांग की, क्योंकि उन्हें लगा कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर एक और मौका फाने के लायक है। सनम तेरी कसम की फिर से रिलीज ने पूरे भारत में धूम मचा दी, यह साबित करते हुए कि फैंस की ताकत किसी भी फिल्म को रातो- रात सुपरहिट करा सकती है। कई महीनों से फैंस फिल्म के मुख्य अभिनेता हर्षवर्धन राणे को मैसेज कर रहे थे और इस पसंदीदा रोमांटिक ड्रामा को दोबारा रिलीज करने की मांग कर रहे थे। जिस वजह से 23 जनवरी 2025 को राणे ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और फैंस से कहा कि वे प्रोड्यूसर्स को टैग करें और अपनी बात जोर से रखें। इसका नतीजा जबरदस्त रहा।

काश पटेल ने भगवद गीता पर ली एफबीआई निदेशक की शपथ, ट्रम्प के माने जाते हैं नजदीकी



नई दिल्ली, एजेंसी। काश पटेल ने अमेरिका के नौवें संघीय जांच ब्यूरो निदेशक के रूप में शपथ ग्रहण की। उनकी नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दी थी। शपथ के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इतिहास में सबसे बेहतरीन FBI निदेशक के रूप में याद किए जाएंगे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित शपथ समारोह में अटॉर्नी जनरल पाम बॉडी ने यह प्रक्रिया संपन्न कराई। इस मौके पर पटेल ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। गुरुवार को सीनेट ने 51-49 के मामूली बहुमत से उनकी नियुक्ति को पुष्टि की, जिसमें दो रिपब्लिकन सीनेटर– मेन की सुसान कॉलिन्स और अलास्का की लिसा मुकोव्स्की ने उनके खिलाफ वोट दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि वे इस पद पर अब तक के सबसे शानदार निदेशक साबित होंगे। FBI एजेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। समारोह में टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज और ओहियो के प्रतिनिधि जिम जॉर्डन सहित कई रिपब्लिकन सांपद मौजूद थे, जैसा कि एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट

फर्जी गन लाइसेंस मामले में आईएसएस राजीव रंजन के 7 ठिकानों पर सीबीआई की रेड

नई दिल्ली, एजेंसी। वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी राजीव रंजन के खिलाफ सीबीआई ने आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक की संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर लिया। उनके खिलाफ फर्जी गन लाइसेंस मामला भी दर्ज है। सीबीआई ने बुधवार को गुरुग्राम, दिल्ली और श्रीनगर के सात ठिकानों की तलाशी ली। श्रीनगर सचिवालय में स्थित उनके कार्यालय की भी जांच की गई है। यह छापेमारी फर्जी गन लाइसेंस मामले में भूमिका निभाने को लेकर की गई।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने राजीव रंजन के खिलाफ चार दिन पहले 17 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी एक मामला चल रहा है। यह दोनों मामले फर्जी गन लाइसेंस मामले में उनकी भूमिका के उजागर होने के बाद दर्ज किए गए। वे 2020 में भी गिरफ्तार किए गए थे फिर उन्हें फरवरी 2021 में बहाल कर दिया गया था।

फिलहाल वे जम्मू कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग में सचिव के पद पर

पदस्थ हैं।सीबीआई ने उन्हें जब फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच के सिलसिले में मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। उस समय वे मे ट्रोपोलिटन रेग्युलेटरी अथॉरिटी के सीईओ और जम्मू विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर थे। उनकी गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए प्रदेश प्रशासन ने उन्हें निलंबित किया था। अदालत में जमानत मिलने के बाद फरवरी 2021 में उन्हें पुनर्बहाल किया गया। केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में राजीव रंजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2010 बैच के आईएसएस राजीव रंजन ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से कहीं अधिक की संपत्ति अर्जित की है। वे अपनी संपत्ति के स्रोतों का कोई संतोषजनक ब्योरा नहीं दे पाए। समझा जा रहा है कि फर्जी गन लाइसेंस जारी करने के एवज में उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा कमाया। श्रीनगर स्थित उनके सचिवालय से सीबीआई के अधिकारियों ने उनके लेन-देन और गन लाइसेंस मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए।

भोपाल में मुंबई के कई फिल्मी कलाकार मौजूद रहे

आकाश-पिंकी शर्मा को आशीर्वाद देने पहुंचे कई फिल्मी हस्तियां एवं कई राजनीतिक लोग एवं समाजसेवी

भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोड्यूसर एवं निर्माता मंजू गौतम के पुत्र आकाश गौतम और पिंकी शर्मा के विवाह समारोह में मुंबई की कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं। श्रीमती मंजू गौतम ने बताया कि प्रमुख रूप से फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो महाभारत के अर्जुन फिरोज खान कॉमेडियन दर्शन कुमार सुनील पाल कॉमेडियन वी आई शर्मा, पार्श्व मनोज ममता पी सर मसूर कॉमेडियन उदय दाईया एवं मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं क्षेत्रीय विधायक

रघुवंशी,सहित बड़ी संख्या में फिल्म मस्ती एवं स प ति न ि ध समाजसेवी इस कार्यक्रम में मौजूद होकर बर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर उमेश चंद्र गौतम , फिल्म प्रोड्यूसर निर्माता श्रीमती मंजू गौतम सूरज गौतम महाकालेश्वर स्टेट ने सभी का धन्यवाद दिया।

‘छावा’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 7 दिन में 219 करोड़ का कलेक्शन

मुंबई। विक्री कौशल और अक्षय खन्ना स्टारर ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म ‘छावा’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 14 फरवरी को रिलीज हुई यह फिल्म अपने पहले दिन ही 31 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग के साथ दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। अब रिलीज के 7वें दिन भी फिल्म का कमाई का सिलसिला जारी है और इसका कुल नेट कलेक्शन 219.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फिल्म का आला लाक्ष्य अब 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिकल् की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘छावा’ ने 7वें दिन यानी गुरुवार को 22 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इस दिन सिनेमाघरों में फिल्म की औसत ऑक्यूपेंसी 27.96 प्रतिशत रही। सुबह के शो में 17.25

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन 2047 के विकसित भारत के निर्माण में कृषि व किसान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी : सुमन बेरी

2047 के विकसित भारत के निर्माण में कृषि व किसान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी : सुमन बेरी



पालनपुर/अहमदाबाद। वृद्धि करने के लिये सतत प्रयासरत है। उनका मानना है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिये हमें विकसित समाज की आवश्यकता है। जिसके लिये कृषि व किसान के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। कृषि व किसान की समृद्धि से ही ग्राम समृद्ध बनेगा और जब ग्राम समृद्ध होगा तो देश की समृद्धि व खुशहाली बढ़ेगी। श्री बेरी ने आगे कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय किसान संघ जैसे राष्ट्र हित की सोच के साथ किसान हित सर्वोपरि रखने वाले किसान संगठनों के योगदान की आवश्यकता है। जिससे कृषि, कृषिान, गांव व देश समृद्धिशाली व विकसित बन सकेगा।इससे पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री बेरी ने अधिवेशन परिसर में किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बंदी नारायण चौधरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र के साथ गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर आधारित लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एक हार का सामना कर चुकी पाकिस्तानी टीम दबाव में, रविवार को भारत से है मुकाबला

दुबई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के महा-मुकाबले में भारत और पाकिस्तान जब रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिय में आमने-सामने होंगे तो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम की निगाह सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर टिकी होगी जबकि मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाली टीम दुर्निर्मित से जल्दी बाहर होने से बचने की कोशिश करेगी। भारत ने जहां अपने पहले मैच में बांग्लादेश को छह विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की वहीं पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से 60 रन से करारी हार का सामना करना

पड़ा था।उपमहाद्वीप की इन दोनों टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मुकाबला 2017 में फाइनल में हुआ था जिसमें पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की थी। रिजवान और उनके साथी लंदन में मिली उस जीत से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे लेकिन उसके पड़ा था।उपमहाद्वीप की इन दोनों टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मुकाबला 2017 में फाइनल में हुआ था जिसमें पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की थी। रिजवान और उनके साथी लंदन में मिली उस जीत से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे लेकिन उसके

धोनीवर्स और उसके भरोसेमंद राज: धोनी के बालों की स्ट्रेटजी, जो आप बेशक जानना चाहेंगे!

मुंबई, एजेंसी। जब पावर कपल एमएस धोनी और साक्षी एक साथ आते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कुछ खास होने वाला है – इस बार, यह अवसर स्वाभाविक रूप से शानदार दिखने के लिए है, जिसका श्रेय गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स को जाता है। अपने नवीनतम टीजर में, उनके बीच की चंचल नोक-झोंक ने सुखियां (और आपका दिल) चुरा ली। जब साक्षी धोनी को उनके अंतहीन कैडिड इंटरव्यू को लेकर चिढ़ाती हैं, तो वह खुद को यह बताने से नहीं रोक पाती कि कैसे किसी ने हाल ही में उनसे पूछा था कि वह 43 साल की उम्र में भी 30 साल के कैसे दिखते हैं। उनका जवाब? बालों का कलर और दाढ़ी का कलर।

गुजरात को इस साल 30 नए आईएसएस अधिकारी मिलेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात प्रशासन ने राज्य विधानसभा में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर चिंता व्यक्त की है। गुजरात विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान प्रवक्ता और मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में आईएसएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 313 है। हालांकि, इसमें से 14 अधिकारी वर्तमान में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं और 56 पद रिक्त हैं। राज्य प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पदों को भरना और अधिकारियों की नियुक्ति करना बहुत जरूरी है। अगर अधिकारियों की कमी या पद रिक्त हैं तो प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य विधानसभा ने अधिकारियों के रिक्त पदों को लेकर चिंता जताई है।उन्होंने कहा कि फरवरी-2025 के दौरान कुल 22 आईएसएस अधिकारी, जिनमें पदोन्नति के माध्यम से एससीएस (राज्य सिविल सेवा) के 20 अधिकारी और चयन के माध्यम से गैर-एससीएस अधिकारियों में से 2 शामिल हैं, राज्य सरकार को उपलब्ध होंगे, साथ ही अक्टूबर-2025 तक सीधी भर्ती के माध्यम से अनुमानित 8 आईएसएस अधिकारी, कुल 30 आईएसएस अधिकारी होंगे। आईएसएस (कैडर) नियम 1954 के अनुसार, आईएसएस संरचना केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय की जाती है। जिसकी हर पांच साल में समीक्षा की जाती है। वर्ष 2018 में की गई अंतिम समीक्षा के अनुसार, वर्तमान में आईएसएस कैडर में 313 पद हैं।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भारत का पहला 3डी-फ़्लिटेड जी+1 विला पेश किया

पुणे। देश के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने पुणे के मान हिजेवाड़ी स्थित गोदरेज ईडन एस्टेट में भारत का पहला 3डी-फ़्लिटेड त्त+1 विला पेश किया है। यह परियोजना द्वास्ता इंजीनियरिंग के सहयोग से पूरी की गई है। अत्याधुनिक 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए, कंपनी ने डिजाइन, दक्षता और स्थायित्व में नए मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे रियल एस्टेट उद्योग में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह विला एड्रिटव मैन्यूफैक्चरिंग तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है, जो 3डी प्रिंटिंग की क्षमता को घर निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में दर्शाता है।

मोदी के आगमन से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता की गारंटी

सरयूसुत मिश्रा

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हर राज्य में होती है लेकिन जिस राज्य में इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं, उस राज्य की जीआईएस की सफलता की गारंटी होती है। जिस जीआईएस में पीएम मोदी हो उसमें देश का कौन सा इन्वेस्टर नहीं पहुंचना चाहेगा? सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इन्वेस्टर्स समिट के लिए पीएम का समय मिल जाना ही, उनकी बड़ी सफलता मानी जाएगी। एमपी में पहले भी जीआईएस होती रही है। एक दो में पीएम भी शामिल हुए हैं लेकिन कई समिट में पीएम का आना नहीं हुआ।

एमपी में इन्वेस्टमेंट के लिए रीजनल समिट करने के बाद देश के कई हिस्सों में सीएम मोहन यादव ने रोड शो एवं इन्वेस्टर्स से चर्चा की। विदेश यात्राएं भी कीं। उनकी सारी तैयारी और भूमिका का अंतिम लक्ष्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पूरा हो सकता है। राजनीतिक रूप से तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन के साथ ही मुख्यमंत्री का अपना पॉलिटिकल टारगेट सफल हो गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी समिट के एक दिन पूर्व राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। यह पहला अवसर है जब पीएम, बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। पीएम का संवाद कई मायने रखता है। पीएम की कार्यशैली ऐसी है कि, उनके हर कदम के मायने परिणाम के बाद ही स्पष्ट होते हैं। उनकी वकिंग और शैली को समझने में पॉलिटिकल पंडित भी चूक जाते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि, एमपी में इन्वेस्टमेंट की अनंत संभावनाएं हैं। यह संभावनाएं ही बताती है कि, अभी तक इनका दोहन नहीं किया गया है। हर जीआईएस में पंच लाइन बदल दी जाती है। अभी तक पयूचर रेडी स्टेट कहा जा रहा था और अब अनंत संभावनाओं का प्रदेश कहा जा रहा है।

जीआईएस की तैयारी में प्रशासन का अतिउत्साह भी देखा जा रहा है। राजधानी को सजाया संवारा जा रहा है, भिखारियों को भगाया जा रहा है, सड़कों को साफ सुथरा किया जा रहा है। जहां कचरा दिख सकता है वहां नेट भी लगाया जा रहे हैं। सड़कों के किनारे चित्रकारी भी हो रही है। होर्डिंस पर तो जीआईएस के ही पोस्टर दिखाई पड़ते हैं। होर्डिंग पर अनंत संभावनाएं दिखाना जितना आसान है, जमीन पर इन्वेस्टमेंट उताना ही कठिन है।

जीआईएस से शुरू इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव जमीन पर उतरने के लिए ब्यूरोक्रेटिक कमिटीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। असल इंग्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी के ही हाथ में होता है। एमपी में इन्वेस्टमेंट का इतिहास तो बहुत सुखद नहीं रहा है। जीआईएस तो हर साल होती है लेकिन उनके नतीजे जमीन पर दिखाई नहीं पड़ते हैं।

इन्वेस्टमेंट की सबसे बुनियादी बात इन्वेस्टर के लिए



होते हैं। इनका आकलन तो तब होता है जब जमीन पर पहुंचते पहुंचते यह प्रस्ताव अपनी मौत मर जाते हैं।

जब भी जीआईएस करीब आती है तब सरकारें नई-नई नीति लाती हैं। MSME के लिए पॉलिसी आती है और स्टार्टअप की भी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी नई पॉलिसी घोषित की है। पॉलिसी के मामले में मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से पीछे नहीं हो सकता। जमीन पर इन्वेस्टमेंट के मामले में जरूर मध्य प्रदेश को अभी बहुत आगे जाना है।

समिट के लिए शहर को सजाने संवारने से ज्यादा अगर शासन-प्रशासन इस बात को साबित करें कि, मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से इन्वेस्टर्स के लिए पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर सस्ता है, उद्योगों में कास्टिंग कम आएगी। जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे स्वागत से नहीं, लागत की कमी से प्रभावित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश देश के केंद्र में है। जमीन तो यहां पर्याप्त मात्रा में है लेकिन फिर भी अभी तक प्रदेश का औद्योगीकरण वांछित स्तर तक नहीं हो पाया तो इसके पीछे कोई बुनियादी ऐतिहासिक कारण ही होंगे। जब तक इन कारणों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक जीआईएस के सफल आयोजन से भी ज़मीनी हकीकत नहीं बदली जा सकेगी।

मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से हुई है। पहली समिट खजुराहो में आयोजित की गई थी। उसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में कोई साल नहीं था जबकि तद्दुस् नहीं आयोजित की गई हो। हर साल कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव भी प्रचारित किए जाते रहे हैं लेकिन जमीन पर वास्तविकता अगर बदली होती तो आज फिर सरकार को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि, एमपी अनंत सम्भवानाओं का प्रदेश है।

अब तक सारी संभावनाओं का दोहन हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कमिटीमेंट दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन पॉलिसी के लेवल पर बेहतर प्रयास भी तब तक सफल नहीं होंगे जब तक ब्यूरोक्रेटिक कमिटीमेंट सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर ब्यूरोक्रेटिक कमिटीमेंट सुधारना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के लिए यही सबसे सही समय है, जब देश के प्रधानमंत्री का प्रदेश के विकास के लिए कमिटीमेंट जग जाहिर है। 'मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी', भाजपा की नई सरकार के गठन का आधार रहा है। भिखारी भगाने से अगर इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित हो सकता है तो किसी राज्य में भिखारी नहीं होते। भविष्य और संभावनाओं में जीते हुए तो मनुष्य अपना वर्तमान गँवा देता है। जीना वर्तमान में पड़ेगा। ब्रांडिंग संभावनाओं की नहीं, वर्तमान सुविधाओं की करना होगी।



सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा बेस्ट फॉर जीआईएस को डिजिटल ई-बुक का लोकार्पण किया गया। खेल, युवा एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारांग और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप, पीएस एमएसएमई राघवेंद्र सिंह जी। एमएसएमई के साथ चर्चा के दौरान सीएम हाउस में दिव्या अत्री जी, अजय देवगानी जी, विजय गौर जी और डॉ. स्मृति राशि मौजूद रहें।



ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान वॉटर स्पोर्ट्स के प्रदर्शन से आकर्षण का केंद्र बनेगा बड़ा तालाब

भोपाल। ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान भोपाल का बड़ा तालाब वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के चलते विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारांग ने शुक्रवार को बोट क्लब पर तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारांग ने बताया कि 23, 24 व 25 फरवरी को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ी विभिन्न रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे, जो देश-विदेश से आए डेलिगेट्स को आकर्षित करेगा।



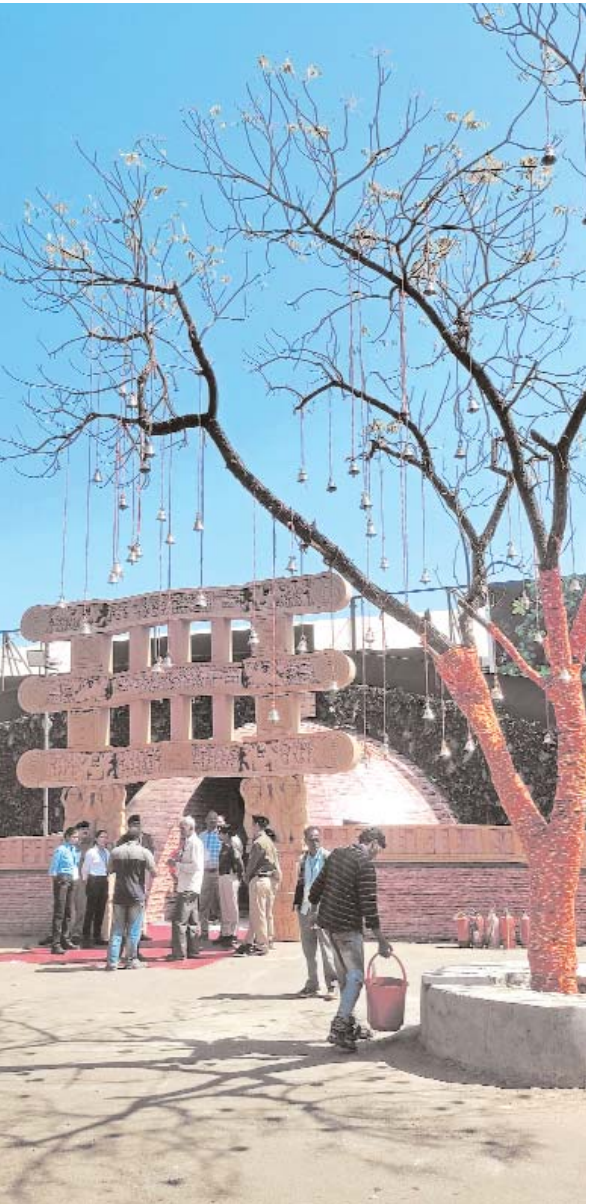
सैलिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और कैनो सलालम वॉटर स्पोर्ट्स से होगा डेलिगेट्स का भव्य स्वागत : मंत्री श्री सारांग ने जानकारी दी कि समिट के दौरान वीआईपी रोड की ओर से बड़े तालाब में सैलिंग बोट पर लगे भव्य बैनर के माध्यम से डेलिगेट्स का स्वागत करेगा। इस अनूठे आयोजन को वीआईपी ब्रिज से ही डेलिगेट्स देख सकेंगे। इस दौरान सैलिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और कैनो सलालम जैसे वॉटर स्पोर्ट्स प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होंगे। इसके साथ ही बोट क्लब पर विशेष साज-सज्जा भी की जायेगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सजी राजधानी जीआईएस में दिखेगी मप्र की सांस्कृतिक विरासत की झलक

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में निवेशकों, उद्योगपतियों और अतिथियों को प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का अनुभव कराने के लिए विशेष रूप से संयोजित अमृतस्य मध्यप्रदेश नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विविधता और पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को प्रसिध्द कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में 100 से अधिक कलाकार अनूठे रूप में दर्शित करेंगे। इसके साथ ही आयोजन स्थल इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में प्रदेश के

पारंपरिक और स्थानीय लोकनृत्य, मटकी नृत्य, करमा जनजातीय नृत्य आदि की प्रस्तुति एक विशेष आकर्षण होगी। जीआईएस के दौरान अतिथियों को मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों की संगीतमयी अनुभूति करायी जाएगी। उनके मध्यप्रदेश आने के अनुभव को अविस्मरणीय बनाने के लिए कई मनमोहक कार्यक्रम अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह प्रयास प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयोजन में 23

फरवरी को ताज लेक फ्रंट होटल में शाम 6:30 बजे से बांसुरी, सरोद, सारंगी और जुगलबंदी जैसी संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। समिट के पहले दिन 24 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में सुबह 8 बजे से स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते लोक कला दलों की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। इसी दिन ओडीओपी मंच और मध्यप्रदेश पेवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें गोंड और भील जनजातियों की लोक संस्कृति एवं बुदेलखंड व चंबल अंचल की विरासत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। शाम को गाला डिनर के दौरान लोकोंचल नृत्य बधाई, मटकी, जनजातीय नृत्य करमा के साथ विशेष अमृतस्य मध्यप्रदेश नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर विभिन्न मंचों पर लोकगीत, जनजातीय संगीत और पारंपरिक लोक नृत्य का मंचन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये अतिथि निवेशकों को प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत परंपरा और उससे हमारा जुड़ाव को नजदीक से अनूठे अंदाज में देखने को मिलेगा।



प्रदेश के कई जिलों के तापमान में आई गिरावट

भोपाल निग्न। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां लगातार तापमान बढ़ रहा था वहीं अचानक से कई जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है।

शनिवार यानि आज भोपाल-ग्वालियर में बादल छा सकते हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। वर्तमान में दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक



सकुल्लेशन सिस्टम है। वहीं, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में भी मौसम बदला है। शुक्रवार से दिन के पारे में गिरावट का दौर शुरू हो गया। प्रदेश में शुक्रवार को पारे में उतार देखने को मिला। कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, रायसेन, रतलाम, खजुराहो, नरसिंहपुर, उमरिया में पारे में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, गुरुवार-शुक्रवार की रात में भी पारे में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, 24 फरवरी को उत्तर-पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। जिसका असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है।